Seventeenth Loksabha

>

Title: Need to withdraw the decision to privatise Nagarnar Steel Plant in Chhattisgarh-laid.

श्री दीपक बैज (बस्तर): खनिज सम्पदा से भरपूर छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले का वर्षों से दोहन हुआ है। केंद्र सरकार एनएमडीसी के नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण कर रही है। 20 हजार करोड़ से अधिक खर्च करके तकरीबन 15 वर्षों से निर्माणाधीन प्लांट से धुंआ निकलने वाला था पर केंद्र सरकार इसे बेच रही है। प्लांट हेतु 610 हैक्टेयर जमीन 15 वर्ष पूर्व किसानों से अधिग्रहित है। भूमि अधिग्रहण के समय किसानों एवं सरकार के मध्य समझौता हुआ था कि भूमि के बदले प्लांट में स्थायी नौकरी प्रदान की जाएगी, पर समझौते के अनुसार, प्लांट में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को स्थायी नौकरी में हिस्सेदारी नगण्य दी गई। आदिवासियों के नैसर्गिक अधिकारों हेतु यहां पेसा कानून 1996 लागू है। पर नियमों के विपरीत प्लांट का निजीकरण से क्षेत्र में विरोध है। किसानों के साथ विश्वासघात है। मेरी मांग है कि नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण रुके और इसमें स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, जिससे क्षेत्र का विकास हो।